		सदस्य होते है । यह समिति राज्य स्तर पर नीति संबंधी निर्देश देती है तथा पनधारा विकास परियोजना को समर्थन प्रदान करती है ।
	2. राज्य स्तरीय परियोजना संस्वीकृति एवं कार्यान्वयन समिति	राज्य के मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी आदि के प्रभारी सचिव इसके सदस्य होते है । यह समिति पनधारा विकास परियोजना के लिए मंजूरी जारी करती है तथा उनके कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करती है ।
जिला स्तर	जिला स्तरीय परियोजना आयोजना एवं कार्यान्वयन समिति	जिला समाहर्ता इस समिति के अध्यक्ष होते है तथा जिले के मुख्य विकास अधिकारी और जिला स्तर के संबद्ध विभागों के अधिकारी इसके सदस्य होते है । इस समिति का उत्तरदायित्व पनधारा विकास दलों द्वारा तैयार की गई पनधारा विकास परियोजनाओं की संवीक्षा करना तथा उन्हें राज्य स्तर की संस्वीकृति समिति के अनुमोदन के लिए सिफारिश करने का है । यह समिति परियोजना के निर्विघ्न क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए भी जिम्मेवार है ।
पनधार स्तर	1. पनधारा विकास दल	कृषि, वानिकी, पशुपालन, बागवानी, मृदा संरक्षण विभागों से लिए गए अधिकारियों का यह एक बहुआयामी दल है । यह बहुआयामी दल विभिन्न पनधारा विकास क्रियाकलापों के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए जिम्मेवार है ।

धान का उत्पादन

1552. **श्री प्रमोद महाराज :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि धान का उत्पादन बढ़ाने और इसकी क्वालिटी में सुधार करने हेतु क्या प्रयत्न किए जा रहे है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : चावल के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 24 चावल उत्पादक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित एकीकृत चावल विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है । इस योजना के माध्यम से उच्च उत्पादक किस्मों के प्रमाणित बीजों, सूक्ष्म पोषकों खरपतवार नाशकों, पौध रक्षण रसायनों, पौध रक्षण उपकरणों, उन्नत कृषि औजारों आदि के उपयोग पर किसानों को सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें चावल उत्पादन की उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालय चावल की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए सतत तथा क्रमबद्ध प्रयास कर रहे है ।

Comparative profits between farm and milk product sectors

15S3. SHRI SOM PAL:
SHRI SARADA MOHANTY:
Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that producers' profits under crops in the farm sector are still superior to those of milk production on per hectare land basis;

(b) if so, whether Government have made any study on the comparative returns pattern for major crops and milk;

(c) if so, what are the details thereof: and

(d) what steps are being taken to improve the return from milk production ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) It is difficult to compare producers' profit under crops in the farm sector and those of milk production on per hectare land basis due to various multiple input-output factors responsible for their production.

(b) and (c) NDRI (1976-77 to 1978-79) have been conducting various studies to study Income and investment pattern in dairy and crop enterprises. It has been observed that the average cost for arable unit (of 2 acres) is Rs. 2539 and for dairy unit (3 milk cows and one acre of intensive farming) is Rs. 1438. The corresponding annual return from each of these programmes is Rs. 2184 and 1096 respectively.

(d) The following steps are being taken to improve the return from milk production:—

(1) Genetic improvement of nationally important cattle breeds by selective breeding in their hometracts and up-grading in other selected areas;

(2) Cross-breeding of non-descript cattle with exotic dairy breeds:

(3) Genetic improvement of important buffaio breeds by selective breeding and upgrading of non-descript buffaloes in other areas for improvement in milk yields;

(4) Development of feed and fodder resources;

(5) Organisation of effective animal health services to support the production programme; and

(6) Implementation of Operation Flood Programme.

देश में प्रति पशु दुग्ध का औसत उत्पादन

1554. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से देश का विश्व में तीसरा स्थान है जबकि विश्व भर में पायी जाने वाली कुल भैंसों में से 50 प्रतिशत भारत में पायी जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में दुध का उत्पादन तो बढ़ा है परंतु प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की दर में विशेष बढ़ोतरी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में देश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन की दर क्या है और भविष्य में इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी नहीं । दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है ।

(ख) और (ग) जी हां । यह सही है कि देश में कुल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है । वर्तमान उत्पादन 58.6 मिलियन टन है । प्रति गाय 1.158 किलो ग्राम प्रति दिन के हिसाब से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है । नस्ल वार दुग्ध उत्पादन के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते । फिर भी, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 70 मिलियन टन कुल दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

देश में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता

1555. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एच० डी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने सरकार को देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कतिपय सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और इस मामले में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (घ) पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इण्डस्ट्री ने मार्च, 1993 में नई दिल्ली में "कृषि में उभरते मुद्दे" पर एक सेमिनार का आयोजन किया था । चैम्बर ने सेमिनार की मसौदा सिफारिशें जानकारी हेतु भेज दी हैं । उत्पादकता से संबंधित सिफारिशें वर्षासिंचित और बारानी क्षेत्रों में कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र-प्रौद्योगिकी पर अधिक जोर देने, श्रम उत्पादकता में वृद्धि करने पर उचित ध्यान देने, छोटे और सीमांत किसानों के लिए सहकारी-कृषि का संगठन करने, छोटी जोतों हेतु उचित प्रौद्योगिकी तथा नवीनतम हाई-टेक जैव-प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के जरिए नए किसानों की खेती में वृद्धि करने पर बल देती है ।

14 मई, 1993 को सभा-पटल पर रखे गए कृषि नीति संकल्प के प्रारूप को तैयार करते समय इन सिफारिशों पर विचार किया गया था ।

कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण

1556. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी संसदीय समिति ने देश के कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण की गिरती हुई हालत पर अपनी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त समिति ने अगले पांच वर्षों के लिए कृषि तथा इससे संबंधित क्षेत्र में 1,25,000 करोड़ रूपए की राशि का निवेश करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सुझाव को कार्यान्वित करने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) आठवीं योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि कुल निवेश में कृषि के हिस्से को सातवीं योजना के 11.23 प्रतिशत से बढ़ाकर आठवीं योजना में 18.65 प्रतिशत कर दिया जाए ।